

उत्तर प्रदेश शासन

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग,

पत्र संख्या २०१ / ६६-२००६-१३४ अ०प्रा०वि०वि० / ०६

लखनऊ : दिनांक : २१ मई, २००६

कार्यालय ज्ञापन

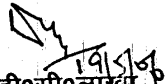
शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि नक्सलप्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु क्षेत्र में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा (प्राथमिक विद्यालय से इन्टर कालेज तक), अस्पतालों के निर्माण हेतु एक अवस्थापना योजना बनाई जायेगी। नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बनायी जाने योजना के लिये प्रदेश बजट से धनराशि की व्यवस्था की जायेगी तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के नीति निर्धारण, अनुश्रवण, समीक्षा तथा समन्वय हेतु निम्नानुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है :-

०१-माननीय कृषि मंत्री जी, उ०प्रा०शासन	अध्यक्ष
०२-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	उपाध्यक्ष
०३-प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०४-प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०५-प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०६-प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०७-प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०८-प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
०९-प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
१०-प्रमुख सचिव/सचिव, थिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
११-प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
१२-प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ०प्रा०	सदस्य
१३-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
१४-प्रमुख सचिव/सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्रा०शासन	संयोजक/ सदस्य

उपर्युक्त समिति को नक्सलप्रभावित योजनाओं के चिन्हाकन, मूल्यांकन, समीक्षा तथा अनुश्रवण आदि करने से सम्बन्धित समस्त कार्य व अधिकार प्राप्त होंगे।

२- अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग में समग्र ग्राम्य विकास योजना का कार्य भी संचालित किया जा रहा है। समग्र ग्राम्य विकास योजना के कार्यों के लिये भी समिति अधिकृत होगी जो प्रस्तावित कार्यों के लिये अधिकारों का प्रयोग करते हुये समय पर गाँवों के समग्र विकास के बारे में संतुष्टीकरण एवं मूल्यांकन तथा समीक्षा, अनुश्रवण आदि करने से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

३- समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जायेंगी परन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार इस समिति की बैठक अनिवार्य होगी। समिति के निर्देश व निर्णय सभी सम्बन्धित विभागों, मण्डलायुक्तों, त्रिभागाध्यक्षों तथा जिलाधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे। अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, योजना का समन्वयक विभाग होगा।



(डी०सी०लाखा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या 20 | (1) / - तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 01- माननीय कृषि मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 02- माननीय मंत्री जी, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 03- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 04- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 05- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
- 06- प्रमुख सचिव / सचिव, गृह / वित्त / नियोजन / ऊर्जा / लोक निर्माण / वन / शिक्षा / नगर विकास / ग्राम्य विकास / चिकित्सा / सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
- 07- सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 08- सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 09- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- मण्डलायुक्त, मीरजापुर / वाराणसी / आजमगढ़ / गोरखपुर।
- 11- जिलाधिकारी, मीरजापुर / सोनभद्र / चन्दौली / बलिया / गाजीपुर / मऊ / देवरिया, कुशीनगर।
- 12- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक मीरजापुर / सोनभद्र / चन्दौली / बलिया / गाजीपुर / मऊ / बलिया / देवरिया / कुशीनगर।
- 13- प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से


(विजय कुमार त्रिपाठी)
विशेष सचिव